



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2018/पौष 28, 1939

No. 26]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2018/PAUSHA 28, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2018

फा.सं. 8(34)/2017-डीबीए-II/एनईआर.—सरकार द्वारा का.जा. सं. 10(3)/2007/डीबीए-II/एनईआर दिनांक 01.04.2007 के माध्यम से अधिसूचित 'पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी), 2007' के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित) में औद्योगीकरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और रियायत पैकेज अनुमोदित किया गया था। उपर्युक्त नीति के अनुसरण में, अधिसूचना सं. 10(3)/2007/डीबीए-II/एनईआर दिनांक 27.07.2007 की अधिसूचना के जरिए केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना अधिसूचित की गई है तथा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12.09.2007, 21.09.2007 और 22.11.2016 के जरिए इसमें संशोधन/ विस्तार किया गया है।

2. दिनांक 27.7.2007 की उपर्युक्त अधिसूचना के पैरा 5 में आंशिक संशोधन करते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक किन्तु 500 करोड़ रुपए तक की केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता हेतु पात्र प्रस्तावों को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

डॉ. वंदना कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2018

F. No. 8(34)/2017/DBA-II/NER.— The Government had approved a package of incentives and concessions to promote industrialization and investment in the North East Region including (Sikkim) under the “North East Industrial and Investment Promotion Policy (NEIIPP), 2007”, which was notified vide O.M. No. 10(3)/2007/DBA-II/NER dated 01.04.2007. In pursuance of the above policy, Central Capital Investment Subsidy Scheme has been notified vide Notification No. 10(3)/2007/DBA-II/NER dated 27.07.2007 and subsequently amended/ amplified vide Notification of even number dated 12.09.2007, 21.09.2007 and 22.11.2016.

2. In partial modification of para 5 of the above notification dated 27.07.2007, it has now been decided by the Government that the proposals which are eligible for Central Capital Investment Subsidy higher than Rs.30 crore but upto Rs.500 crore for each individual industrial unit will be approved by the Minister of Commerce & Industry.

Dr. VANDANA KUMAR, Jt. Secy.